International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

अफ्रीका में भारत की विकास कूटनीति: दक्षिण-दक्षिण सहयोग और रणनीतिक हित

Ms. Seenu
M.A. in Political Science, Independent Researcher, India
Email: seenuduchaniya33@gmail.com
Mob.no. 9813146351

सारांश
अफ्रीका के साथ भारत का विकासात्मक जुड़ाव उसकी व्यापक वैश्विक दक्षिण कूटनीति का एक महत्त्वपूर्ण घटक बन गया है। इसकी जड़ें उपनिवेशवाद-विरोधी एकजुटता, बांडुंग भावना और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में निहित हैं। भारत-अफ्रीका सहयोग धीरे-धीरे राजनीतिक समर्थन और तकनीकी सहायता से आगे बढ़कर बहुआयामी विकास साझेदारी में परिवर्तित हुआ है। यह शोधपत्र स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद से 2026 तक अफ्रीका में भारत के दक्षिण-दक्षिण विकास सहयोग के विकास का अध्ययन करता है, विशेष रूप से 2008 में भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन की स्थापना के बाद की अवधि पर ध्यान केंद्रित करते हुए।
आधिकारिक दस्तावेजों, नीतिगत रिपोर्टों और विद्वतापूर्ण साहित्य पर आधारित गुणात्मक एवं विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए यह अध्ययन भारत के प्रमुख सहयोग माध्यमों—भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम, रियायती ऋण-व्यवस्थाएँ, डिजिटल कनेक्टिविटी परियोजनाएँ, स्वास्थ्य कूटनीति, शैक्षिक सहयोग, व्यापार और निजी क्षेत्र के निवेश—का विश्लेषण करता है।
इसका तर्क है कि भारत का दृष्टिकोण क्षमता-निर्माण, मांग-आधारित परियोजनाओं, अपेक्षाकृत कम शर्तों और दाता–प्राप्तकर्ता पदानुक्रम के बजाय साझेदारी की भाषा पर आधारित है। हालांकि, सीमित वित्तीय क्षमता, परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी, निगरानी की असमानता तथा चीन और पारंपरिक दाताओं के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियाँ भी मौजूद हैं। निष्कर्षतः अफ्रीका में भारत की भविष्य की विश्वसनीयता बेहतर परियोजना-क्रियान्वयन, अधिक पारदर्शिता, अफ्रीकी संघ की प्राथमिकताओं के साथ गहरे सामंजस्य और अफ्रीकी पक्ष की स्वायत्त भूमिका को वास्तविक मान्यता देने पर निर्भर करेगी।

मुख्य शब्द: भारत-अफ्रीका संबंध; दक्षिण-दक्षिण सहयोग; विकास साझेदारी; ऋण-व्यवस्थाएँ; आईटीईसी; वैश्विक दक्षिण; अफ्रीकी विकास।

1. प्रस्तावना

अफ्रीका अपनी जनसांख्यिकीय महत्ता, प्राकृतिक संसाधनों, विस्तृत होते बाजारों, हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक स्थिति और बहुपक्षीय संस्थाओं में बढ़ते प्रभाव के कारण भारत की विदेश नीति में अधिक महत्त्व प्राप्त कर चुका है। अफ्रीकी देशों के साथ भारत का जुड़ाव अब केवल कूटनीतिक सद्भावना या ऐतिहासिक स्मृतियों तक सीमित नहीं है। इसमें विकास सहयोग, व्यापार, निवेश, डिजिटल संपर्क, स्वास्थ्य साझेदारी, क्षमता-निर्माण, समुद्री सहयोग और वैश्विक शासन से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक समन्वय भी शामिल हैं। विदेश मंत्रालय इस संबंध को पारस्परिक सम्मान, समानता और अफ्रीकी प्राथमिकताओं पर आधारित बहुआयामी साझेदारी के रूप में प्रस्तुत करता है। 2008 में आरंभ हुई भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन प्रक्रिया ने इस विस्तारित संबंध को संस्थागत ढाँचा प्रदान किया है।

यह शोधपत्र तीन प्रश्नों पर केंद्रित है: समय के साथ अफ्रीका के साथ भारत का विकास सहयोग किस प्रकार विकसित हुआ है? भारत के दक्षिण-दक्षिण सहयोग मॉडल को पारंपरिक सहायता संबंधों से क्या अलग बनाता है? एक विश्वसनीय और प्रभावी साझेदारी बनाए रखने के लिए भारत को किन सीमाओं और चुनौतियों का समाधान करना होगा? इसका केंद्रीय तर्क है कि भारत का जुड़ाव एकजुटता-आधारित सहयोग और मानव संसाधन विकास से विकसित होकर अधिक रणनीतिक, विविधतापूर्ण और साझेदारी-केंद्रित मॉडल में परिवर्तित हुआ है। फिर भी, इस परिवर्तन का अर्थ यह नहीं है कि भारत पारंपरिक दाता शक्ति बन गया है। क्षमता-निर्माण, किफायती तकनीक, जेनेरिक दवाओं, डिजिटल ज्ञान-साझाकरण और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास अनुभव के क्षेत्रों में भारत की तुलनात्मक भूमिका अधिक मजबूत बनी हुई है।

यह अध्ययन भारतीय और अफ्रीकी संघ के आधिकारिक दस्तावेजों, शिखर सम्मेलन घोषणाओं, संयुक्त राष्ट्र की सामग्री, नीतिगत रिपोर्टों और विद्वतापूर्ण विश्लेषण पर आधारित गुणात्मक पद्धति अपनाता है। इसका दायरा अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी के व्यापक ऐतिहासिक विकास को समेटता है, जबकि 2008 में भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन प्रक्रिया शुरू होने के बाद के घटनाक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह शोधपत्र अफ्रीका को एक समान राजनीतिक या आर्थिक इकाई नहीं मानता। अफ्रीकी देशों की विकास संबंधी आवश्यकताओं, संस्थागत क्षमताओं, क्षेत्रीय प्राथमिकताओं और बाहरी शक्तियों के साथ संबंधों में उल्लेखनीय अंतर हैं।

2. दक्षिण-दक्षिण विकास सहयोग को समझना

दक्षिण-दक्षिण सहयोग से आशय विकासशील देशों के बीच ऐसे सहयोग से है, जो पारस्परिक लाभ, साझा विकास अनुभवों, राष्ट्रीय स्वामित्व, संप्रभुता, समानता, अहस्तक्षेप और शर्तों की अनुपस्थिति पर आधारित होता है। इसका उद्देश्य ज्ञान, कौशल, तकनीक, वित्त और संस्थागत अनुभवों के आदान-प्रदान के माध्यम से वैश्विक दक्षिण के देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है। संयुक्त राष्ट्र दक्षिण-दक्षिण सहयोग कार्यालय इसे ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है, जिसके माध्यम से विकासशील देश तकनीकी जानकारी, संसाधनों और नीतिगत अनुभवों के आदान-प्रदान द्वारा अपने राष्ट्रीय एवं सामूहिक विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हैं।

दक्षिण-दक्षिण सहयोग वैचारिक रूप से पारंपरिक उत्तर-दक्षिण सहायता से अलग है। पारंपरिक सहायता अक्सर दाता देशों की शर्तों, नीतिगत सुधारों की अपेक्षाओं और असमान संस्थागत संबंधों से जुड़ी रही है। इसके विपरीत, दक्षिण-दक्षिण सहयोग कठोर दाता–प्राप्तकर्ता पदानुक्रम से बचने का दावा करता है। इसमें साझेदारी, परामर्श, पारस्परिक सीख और घरेलू स्वामित्व पर बल दिया जाता है। हालांकि, इस अंतर को आदर्श रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। उभरते हुए विकास साझेदार भी आर्थिक, कूटनीतिक और रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाते हैं। उनकी विकास पहल घरेलू कंपनियों के लिए बाजार, संसाधनों तक पहुँच, अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक समर्थन और भू-राजनीतिक प्रभाव को बढ़ावा दे सकती हैं।

भारत के विकास सहयोग को उत्तर-औपनिवेशिक एकजुटता, विकास कूटनीति, सॉफ्ट पावर और रणनीतिक स्वायत्तता के संयुक्त दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। इसका दृष्टिकोण एक ऐसे उत्तर-औपनिवेशिक राज्य के ऐतिहासिक अनुभव को दर्शाता है, जो स्वयं कभी विकास सहायता प्राप्तकर्ता रहा है। इसलिए भारत ने अक्सर अपने बाहरी सहयोग को किसी सार्वभौमिक मॉडल के निर्यात के बजाय

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

विकास संबंधी अनुभवों को साझा करने के रूप में प्रस्तुत किया है। 2019 के ब्यूनस आयर्स परिणाम दस्तावेज़ ने पुनः पुष्टि की कि दक्षिण-दक्षिण सहयोग को राष्ट्रीय स्वामित्व और पारस्परिक लाभ के मार्गदर्शन में रहते हुए उत्तर-दक्षिण सहयोग का पूरक होना चाहिए, उसका विकल्प नहीं (United Nations General Assembly 2019)।

3. भारत-अफ्रीका विकास सहयोग का ऐतिहासिक विकास

अफ्रीका के साथ भारत की वर्तमान साझेदारी की ऐतिहासिक जड़ें गहरी हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय राजनीतिक नेताओं ने पूरे अफ्रीका में उपनिवेशवाद-विरोधी संघर्षों का समर्थन किया और दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव का विरोध किया। 1955 के बांडुंग सम्मेलन और उसके बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने ऐसा राजनीतिक मंच उपलब्ध कराया, जहाँ एशियाई और अफ्रीकी देश उपनिवेशवाद, नस्लवाद, असमानता और वैश्विक शक्ति-संरचनाओं से जुड़ी साझा चिंताओं को व्यक्त कर सके।

शीत युद्ध के दौरान अफ्रीका के साथ भारत का जुड़ाव मुख्यतः राजनीतिक एकजुटता, उपनिवेशवाद से मुक्ति के समर्थन, रंगभेद के विरोध तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन और 77 देशों के समूह के माध्यम से सहयोग से प्रभावित था। तकनीकी सहायता, शैक्षिक छात्रवृत्तियाँ और पेशेवर प्रशिक्षण धीरे-धीरे भारत के जुड़ाव के महत्त्वपूर्ण अंग बन गए। 1964 में स्थापित भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आईटीईसी) वह प्रमुख माध्यम बना, जिसके जरिए भारत ने साझेदार देशों को प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता के अवसर उपलब्ध कराए (Mukhopadhyay 2022)।

1991 में भारत के आर्थिक उदारीकरण ने एक महत्त्वपूर्ण बदलाव लाया। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था ने ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार विविधीकरण, विदेशी बाजारों और रणनीतिक खनिजों तक पहुँच में उसकी रुचि बढ़ाई। इसी समय अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाएँ भी राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन से गुजर रही थीं। इस प्रकार भारत का दृष्टिकोण मुख्यतः वैचारिक संबंध से आगे बढ़कर व्यापार, तकनीक, बुनियादी ढाँचे, निवेश और कूटनीति को समेटने वाली व्यापक विकास साझेदारी में बदल गया।

2008 में भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन की शुरुआत एक प्रमुख संस्थागत मोड़ साबित हुई। 2008 में नई दिल्ली, 2011 में अदीस अबाबा और 2015 में नई दिल्ली में आयोजित शिखर सम्मेलनों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बुनियादी ढाँचे, सूचना प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, शांति और सुरक्षा के क्षेत्रों में संरचित सहयोग का ढाँचा तैयार किया। 2015 का शिखर सम्मेलन विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण था, क्योंकि भारत ने अफ्रीकी साझेदारों के लिए 10 अरब अमेरिकी डॉलर की रियायती ऋण-व्यवस्थाओं, 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता और 50,000 छात्रवृत्तियों एवं प्रशिक्षण अवसरों की प्रतिबद्धता व्यक्त की (Government of India 2021)।

4. अफ्रीका में भारत के विकास सहयोग के प्रमुख माध्यम

4.1 भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम

भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम, जिसे सामान्यतः आईटीईसी कहा जाता है, भारत के क्षमता-निर्माण दृष्टिकोण की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति बना हुआ है। यह विकासशील देशों के सिविल सेवकों, राजनयिकों, इंजीनियरों, स्वास्थ्य पेशेवरों, शिक्षकों, रक्षा कर्मियों और तकनीकी विशेषज्ञों को प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है। अफ्रीकी प्रतिभागियों को लोक प्रशासन, सूचना प्रौद्योगिकी,

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

उद्यमिता, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य प्रबंधन और आपदा-प्रतिक्रिया जैसे क्षेत्रों में भारतीय संस्थानों में अध्ययन के अवसर मिलते हैं।

आईटीईसी का महत्त्व केवल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या में नहीं, बल्कि उसके दीर्घकालिक सामाजिक प्रभाव में निहित है। भारत में प्रशिक्षित अनेक अफ्रीकी पेशेवर बाद में सरकार, कूटनीति, शिक्षा जगत, व्यवसाय और नागरिक समाज में महत्त्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हैं। इससे पेशेवर नेटवर्क बनते हैं और भारत के प्रति सद्भावना मजबूत होती है। बड़े बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की तुलना में क्षमता-निर्माण का प्रभाव अल्पकाल में कम दिखाई दे सकता है, लेकिन समय के साथ यह संस्थागत विकास और जन-से-जन संबंधों को मजबूत कर सकता है।

4.2 ऋण-व्यवस्थाएँ (Lines of Credit)

भारतीय निर्यात-आयात बैंक के माध्यम से दी जाने वाली रियायती ऋण-व्यवस्थाएँ भारत के विकास सहयोग का एक अन्य प्रमुख स्तंभ हैं। इनके माध्यम से परिवहन, ऊर्जा, कृषि, जलापूर्ति, ग्रामीण विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और बुनियादी ढाँचे से जुड़ी परियोजनाओं को समर्थन दिया जाता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने 2026 में बताया कि उसने 42 अफ्रीकी देशों को लगभग 12 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य की 196 ऋण-व्यवस्थाएँ प्रदान की थीं। इन परियोजनाओं में बिजली संयंत्र, चीनी कारखाने, प्रौद्योगिकी पार्क, परिवहन अवसंरचना और शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं।

ऋण-व्यवस्थाएँ विकासात्मक और वाणिज्यिक उद्देश्यों को एक साथ जोड़ती हैं। इनके माध्यम से साझेदार देशों को प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए रियायती वित्त उपलब्ध होता है, साथ ही भारतीय कंपनियों, परामर्शदाताओं और आपूर्तिकर्ताओं के लिए अवसर भी पैदा होते हैं। इस दोहरे स्वरूप का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन आवश्यक है। वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय ऋण-व्यवस्थाओं से वित्तपोषित वस्तुओं और सेवाओं का एक बड़ा हिस्सा भारत से प्राप्त करना होता है। एक्ज़िम बैंक के अनुसार, सामान्यतः अनुबंध मूल्य का कम-से-कम 75 प्रतिशत भारतीय आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त होना आवश्यक है।

यह व्यवस्था प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा दे सकती है, लेकिन इससे स्थानीय खरीद सीमित हो सकती है और प्राप्तकर्ता देशों की विकासात्मक लचीलापन क्षमता कम हो सकती है। इसलिए ऋण-व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि परियोजनाएँ वास्तव में मांग-आधारित, वित्तीय रूप से व्यवहार्य, स्थानीय स्तर पर रखरखाव योग्य और राष्ट्रीय विकास योजनाओं से जुड़ी हों। स्वीकृति, खरीद, क्रियान्वयन और परियोजना पूर्णता में देरी भारत की साझेदारी की सार्वजनिक दृश्यता को कमजोर कर सकती है।

4.3 भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन प्रक्रिया

भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन प्रक्रिया ने अफ्रीकी देशों और अफ्रीकी संघ के साथ भारत के संबंधों को संस्थागत रूप दिया। इसने जुड़ाव को अलग-अलग द्विपक्षीय परियोजनाओं से आगे बढ़ाकर अधिक समन्वित महाद्वीपीय ढाँचे की ओर अग्रसर किया। 2008 के शिखर सम्मेलन में क्षमता-निर्माण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संस्थागत सहयोग पर बल दिया गया। 2011 के शिखर सम्मेलन में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, बुनियादी ढाँचे और क्षेत्रीय संस्थाओं के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हुआ। 2015 के शिखर

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

सम्मेलन ने सतत विकास, जलवायु संबंधी चिंताओं, शांति एवं सुरक्षा और कौशल विकास को जोड़ते हुए एजेंडे को और व्यापक बनाया।

इन शिखर सम्मेलनों ने भारत और अफ्रीकी देशों को वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार, जलवायु न्याय, विकास वित्त और बहुपक्षीय मंचों में विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व पर अपने विचारों का समन्वय करने का अवसर भी दिया। हालांकि, शिखर सम्मेलन की घोषणाओं के बाद समयबद्ध और भरोसेमंद क्रियान्वयन आवश्यक है। संस्थागत संवाद महत्त्वपूर्ण है, लेकिन साझेदारी की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि घोषित प्रतिबद्धताएँ वास्तविक रूप से पूर्ण परियोजनाओं में बदलती हैं या नहीं।

4.4 पैन-अफ्रीकन ई-नेटवर्क और डिजिटल सहयोग

पैन-अफ्रीकन ई-नेटवर्क परियोजना अफ्रीका में भारत की सबसे नवाचारी विकास पहलों में से एक थी। 2009 में औपचारिक रूप से शुरू की गई इस परियोजना ने उपग्रह और फाइबर-ऑप्टिक अवसंरचना के माध्यम से अफ्रीकी संस्थानों को भारतीय विश्वविद्यालयों और अस्पतालों से जोड़ा। इससे दूरस्थ शिक्षा, टेलीमेडिसिन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डिजिटल ज्ञान-साझाकरण संभव हुआ। इस परियोजना का उद्देश्य ई-गवर्नेंस, संसाधन मानचित्रण और सहभागी अफ्रीकी देशों के बीच संचार संपर्कों को समर्थन देना भी था।

इस परियोजना का महत्त्व इस बात में था कि उसने दिखाया कि विकास साझेदारी केवल भौतिक बुनियादी ढाँचे पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। डिजिटल कनेक्टिविटी दूर-दराज के क्षेत्रों तक शैक्षिक और चिकित्सा सेवाएँ पहुँचा सकती है, विशेषकर उन देशों में जहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों, प्रशिक्षित शिक्षकों और तकनीकी संस्थानों की कमी है। भारत-अफ्रीका डिजिटल सहयोग के अगले चरण को अलग-अलग संपर्क परियोजनाओं से आगे बढ़कर डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, परस्पर अनुकूल भुगतान प्रणालियों, डिजिटल पहचान, ई-स्वास्थ्य मंचों, साइबर सुरक्षा और डिजिटल कौशल प्रशिक्षण पर केंद्रित होना चाहिए। इस एजेंडे का निर्धारण भारतीय डिजिटल मॉडलों के साधारण हस्तांतरण के बजाय अफ्रीकी प्राथमिकताओं के आधार पर होना चाहिए। अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र का डिजिटल व्यापार प्रोटोकॉल समन्वित नियमों, सुरक्षित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र, परस्पर अनुकूल प्रणालियों, डिजिटल कौशल और समावेशी डिजिटल परिवर्तन का लक्ष्य रखता है। भारत अफ्रीका की नियामकीय स्वायत्तता और डेटा संप्रभुता का सम्मान करते हुए इस क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता का योगदान दे सकता है।

4.5 स्वास्थ्य, शिक्षा और मानवीय सहयोग

स्वास्थ्य कूटनीति अफ्रीका में भारत की विकासात्मक उपस्थिति का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत बन गई है। भारत किफायती जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करता है, चिकित्सा प्रशिक्षण को समर्थन देता है, छात्रवृत्तियाँ प्रदान करता है और टेलीमेडिसिन पहलों तथा स्वास्थ्य क्षेत्र के सहयोग में योगदान देता रहा है। भारत का औषधि क्षेत्र उन अफ्रीकी देशों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जो संक्रामक और गैर-संक्रामक रोगों के किफायती उपचार की तलाश में हैं।

कोविड-19 महामारी के दौरान भारत की चिकित्सा आपूर्ति, औषधि निर्यात और टीका सहयोग ने स्वास्थ्य साझेदार के रूप में उसकी छवि को मजबूत किया। हालांकि, स्वास्थ्य सहयोग का मूल्यांकन केवल आपातकालीन सहायता के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। सतत सहयोग के लिए स्थानीय विनिर्माण क्षमता, नियामकीय समर्थन, चिकित्सा शिक्षा, आपूर्ति शृंखला की मजबूती और सार्वजनिक स्वास्थ्य

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

अवसंरचना आवश्यक हैं। ब्रुकिंग्स इंडिया के अनुसार, किफायती दवाओं, टीकों, टेलीमेडिसिन और क्षमता-निर्माण के कारण अफ्रीका में भारत का स्वास्थ्य जुड़ाव महत्त्वपूर्ण रहा है, लेकिन इसके लिए संस्थागत और नागरिक समाज के साथ अधिक गहरे जुड़ाव की आवश्यकता है (Brookings India 2015)।

शिक्षा भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है। छात्रवृत्तियाँ, प्रशिक्षण कार्यक्रम, भारतीय विश्वविद्यालय परिसरों और पेशेवर आदान-प्रदान से दीर्घकालिक साझेदारियाँ विकसित हो सकती हैं। भारत की शैक्षिक भूमिका इसलिए विशेष महत्त्व रखती है क्योंकि वह सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, लोक प्रशासन, चिकित्सा और उद्यमिता जैसे विकासशील समाजों के लिए प्रासंगिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत किफायती उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है।

4.6 व्यापार, निवेश और निजी क्षेत्र की भागीदारी

भारत का आधिकारिक विकास सहयोग तेजी से निजी क्षेत्र के निवेश के साथ आगे बढ़ रहा है। भारतीय कंपनियाँ औषधि, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, कृषि, ऑटोमोबाइल, खनन, बैंकिंग, उपभोक्ता वस्तुओं और विनिर्माण के क्षेत्रों में सक्रिय हैं। निजी क्षेत्र की यह उपस्थिति रोजगार सृजित करके, कौशल हस्तांतरित करके और स्थानीय मूल्य श्रृंखलाओं का विस्तार करके आधिकारिक सहायता की पूरक बन सकती है।

हालांकि, व्यापार और निवेश को स्वतः विकास सहयोग नहीं माना जाना चाहिए। उनका विकासात्मक प्रभाव स्थानीय रोजगार, कर संबंधी व्यवहार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व और घरेलू उद्योगों के साथ एकीकरण पर निर्भर करता है। पिछले दो दशकों में भारत-अफ्रीका व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन यह अब भी पेट्रोलियम, खनिज, औषधि और विनिर्मित उत्पादों सहित कुछ क्षेत्रों में केंद्रित है। अधिक मजबूत साझेदारी को केवल वस्तु-आधारित व्यापार के पुराने ढाँचे को दोहराने के बजाय अफ्रीकी औद्योगीकरण का समर्थन करना चाहिए (Sachdeva 2020)।

5. भारत के विकास सहयोग मॉडल की विशिष्ट विशेषताएँ

भारत के सहयोग मॉडल की चार प्रमुख विशेषताएँ हैं। पहली, यह मांग-आधारित साझेदारी और प्राप्तकर्ता सरकारों के साथ परामर्श पर बल देता है। दूसरी, प्रत्यक्ष बजटीय सहायता की तुलना में क्षमता-निर्माण और व्यावहारिक ज्ञान के हस्तांतरण को अधिक महत्त्व देता है। तीसरी, भारत दाता–प्राप्तकर्ता पदानुक्रम के बजाय विकास साझेदारी की भाषा का उपयोग करता है। चौथी, यह उन क्षेत्रों में भारत के अनुभव का लाभ उठाता है, जिनमें कम लागत वाली स्वास्थ्य सेवाएँ, जेनेरिक औषधियाँ, लघु उद्यम, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल शासन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं।

भारत के दृष्टिकोण को ऐतिहासिक संबंधों, प्रवासी भारतीय समुदाय के संपर्कों और साझा उत्तर-औपनिवेशिक अनुभवों से भी लाभ मिलता है। ये कारक भारत को ऐसे साझेदार के रूप में प्रस्तुत करने में मदद करते हैं, जो वैश्विक दक्षिण के अन्य देशों की विकास संबंधी चुनौतियों को समझता है। फिर भी, इस मॉडल को स्वाभाविक रूप से अन्य सभी विकल्पों से अधिक नैतिक या प्रभावी नहीं माना जाना चाहिए। भारत का विकास सहयोग विकासात्मक उद्देश्यों के साथ-साथ राष्ट्रीय हितों को भी आगे बढ़ाता है। इससे बाजारों का विस्तार, भारतीय कंपनियों को समर्थन, कूटनीतिक प्रभाव में वृद्धि, संसाधनों तक बेहतर पहुँच और वैश्विक दक्षिण के नेतृत्व के भारत के दावे को मजबूती मिल सकती है।

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

इसलिए यथार्थपरक मूल्यांकन में भारत द्वारा प्रचारित सिद्धांतों और परियोजनाओं से वास्तव में प्राप्त परिणामों के बीच अंतर करना आवश्यक है। इसकी प्रमुख कसौटी यह होनी चाहिए कि क्या अफ्रीकी साझेदारों को सतत संस्थागत क्षमता, स्थानीय रोजगार, उत्पादक बुनियादी ढाँचा और नीतिगत स्वायत्तता प्राप्त होती है।

6. भारत, चीन और पारंपरिक दाता: एक तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य

भारत की विकास साझेदारी की तुलना अक्सर चीन की भागीदारी और पश्चिमी सहायता मॉडलों से की जाती है। विशेष रूप से बुनियादी ढाँचे के ऋण के मामले में चीन ऐतिहासिक रूप से कहीं बड़े वित्तीय पैमाने पर कार्य करता रहा है। बोस्टन विश्वविद्यालय के चाइनीज़ लोन्स टू अफ्रीका डेटाबेस के अनुसार, 2000 से 2024 के बीच चीनी ऋणदाताओं ने अफ्रीकी सरकारों और क्षेत्रीय संस्थाओं को लगभग 180.87 अरब अमेरिकी डॉलर के 1,319 ऋण प्रतिबद्धताएँ प्रदान कीं।

भारत इस वित्तीय पैमाने की बराबरी नहीं कर सकता। इसकी तुलनात्मक बढ़त तकनीकी प्रशिक्षण, किफायती समाधान, औषधीय सहयोग, सूचना प्रौद्योगिकी और अपेक्षाकृत छोटी विकास परियोजनाओं वाले क्षेत्रों में है। भारत का लोकतांत्रिक अनुभव, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा, निजी क्षेत्र के संबंध और प्रवासी भारतीय नेटवर्क भी जुड़ाव के विशिष्ट माध्यम प्रदान करते हैं।

पारंपरिक पश्चिमी दाताओं के पास सामान्यतः अधिक मजबूत वित्तीय संस्थाएँ, बड़े अनुदान संसाधन और बहुपक्षीय विकास वित्त का गहरा अनुभव होता है। हालांकि, उनकी सहायता शासन संबंधी शर्तों, नीतिगत सुधार के एजेंडे और दाता-निर्धारित प्राथमिकताओं से जुड़ी हो सकती है। भारत अपने दृष्टिकोण को कम हस्तक्षेपकारी और संप्रभुता का अधिक सम्मान करने वाला बताता है। फिर भी, भारत की ऋण-व्यवस्थाओं में वाणिज्यिक तत्व मौजूद हैं और भारतीय परियोजनाएँ राजनीतिक या आर्थिक हितों से पूरी तरह मुक्त नहीं हैं।

चीन के बुनियादी ढाँचा मॉडल के अंतर्गत सड़कें, रेलवे, बंदरगाह, औद्योगिक क्षेत्र और बिजली सुविधाओं जैसी स्पष्ट दिखाई देने वाली परियोजनाएँ विकसित हुई हैं। साथ ही, चीनी ऋण ने ऋण स्थिरता, पारदर्शिता, स्थानीय श्रम और रणनीतिक निर्भरता को लेकर बहस भी पैदा की है। भारत को अपनी अफ्रीका नीति केवल चीन की प्रतिक्रिया के रूप में नहीं बनानी चाहिए। इसके बजाय उसे उन क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए जहाँ वह विश्वसनीय योगदान दे सकता है—कौशल, किफायती तकनीक, स्थानीय संस्थाओं का निर्माण, जलवायु अनुकूलन, डिजिटल सार्वजनिक संसाधन, स्वास्थ्य प्रणालियाँ और अफ्रीकी औद्योगीकरण को समर्थन।

7. चुनौतियाँ और सीमाएँ

अफ्रीका में विकास सहयोग का विस्तार करते समय भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहली चुनौती सीमित वित्तीय क्षमता है। भारत के विकास संसाधन चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और प्रमुख बहुपक्षीय संस्थाओं के उपलब्ध संसाधनों से कम हैं। दूसरी चुनौती परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी है, जो भारतीय परियोजनाओं के मूल्य को कम कर सकती है। प्रशासनिक प्रक्रियाएँ, खरीद संबंधी आवश्यकताएँ, स्थानीय क्षमता की कमी, राजनीतिक अस्थिरता और समन्वय की समस्याएँ परियोजनाओं को पूरा करने में बाधा बन सकती हैं।

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

तीसरी, कुछ अफ्रीकी देशों में भारत की विकास साझेदारी पर्याप्त रूप से दिखाई नहीं देती। अन्य शक्तियों द्वारा वित्तपोषित बड़ी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को अधिक सार्वजनिक ध्यान मिल सकता है, जबकि क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों का प्रभाव तत्काल कम दिखाई देता है। चौथी, भारत को निगरानी और मूल्यांकन की व्यवस्था बेहतर करनी होगी। सफलता का आकलन केवल घोषित परियोजनाओं या विस्तारित ऋण-व्यवस्थाओं की संख्या से नहीं होना चाहिए। इसके बजाय पूर्ण हुई परियोजनाओं, स्थानीय रोजगार, कौशल हस्तांतरण, लैंगिक समावेशन, रखरखाव क्षमता और विकासात्मक परिणामों के आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

अंततः, अफ्रीकी पक्ष की स्वायत्त भूमिका को केंद्रीय स्थान मिलना चाहिए। अफ्रीका बाहरी सहायता का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं है। अफ्रीकी सरकारें, क्षेत्रीय संगठन, नागरिक समाज समूह, व्यवसाय और समुदाय सक्रिय रूप से साझेदारियों पर बातचीत करते हैं और उन्हें आकार देते हैं। भारत की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह अफ्रीकी प्राथमिकताओं की विविधता को पहचानता है या नहीं और अफ्रीका-नेतृत्व वाली क्षेत्रीय पहलों का समर्थन करता है या नहीं।

8. भविष्य की संभावनाएँ और नीतिगत सुझाव

अफ्रीका के साथ भारत के भविष्य के विकास सहयोग को अफ्रीकी संघ के एजेंडा 2063 और अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र के साथ अधिक निकटता से जोड़ा जाना चाहिए। अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र का उद्देश्य महाद्वीपीय बाजार का निर्माण, औद्योगीकरण को बढ़ावा, क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाओं को मजबूत करना और वैश्विक व्यापार में अफ्रीका की स्थिति बेहतर बनाना है। भारत लॉजिस्टिक्स, विनिर्माण साझेदारी, डिजिटल व्यापार अवसंरचना, औषधि उत्पादन, कृषि मूल्य शृंखलाओं और कौशल विकास में निवेश के माध्यम से इन लक्ष्यों का समर्थन कर सकता है।

पहला, भारत को परियोजना निगरानी, पारदर्शी खरीद और ऋण-व्यवस्थाओं पर सार्वजनिक रिपोर्टिंग को मजबूत करके क्रियान्वयन क्षमता में सुधार करना चाहिए। परियोजनाओं के चयन में स्थानीय समुदायों, क्षेत्रीय संस्थाओं और अफ्रीकी तकनीकी विशेषज्ञों के साथ गहरा परामर्श शामिल होना चाहिए। दूसरा, भारत को विशेष रूप से सौर ऊर्जा, स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन, सिंचाई, जल प्रबंधन और आपदा तैयारी के क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा तथा जलवायु-सहनशीलता संबंधी सहयोग का विस्तार करना चाहिए।

तीसरा, भारत को अधिक महत्वाकांक्षी डिजिटल साझेदारी विकसित करनी चाहिए। इसमें डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा, सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति, परस्पर अनुकूल भुगतान प्रणालियों और डिजिटल उद्यमिता को समर्थन शामिल होना चाहिए। चौथा, स्वास्थ्य सहयोग का ध्यान स्थानीय औषधि उत्पादन, चिकित्सा शिक्षा, रोग निगरानी और मजबूत स्वास्थ्य आपूर्ति शृंखलाओं पर होना चाहिए। पाँचवाँ, भारत को महिला उद्यमियों, युवाओं के रोजगार, व्यावसायिक शिक्षा और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विशेष रूप से तैयार कार्यक्रम विकसित करने चाहिए।

भारत को जहाँ उपयुक्त हो, त्रिकोणीय सहयोग का अधिक उपयोग भी करना चाहिए। अफ्रीकी संघ, अफ्रीकी विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और अन्य विकास संस्थाओं से जुड़ी साझेदारियाँ अतिरिक्त वित्त, तकनीकी सहायता और जवाबदेही उपलब्ध करा सकती हैं। भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष ऐसे सहयोग के महत्त्व को दर्शाता है। अप्रैल 2026 तक इस कोष ने स्थानीय नेतृत्व और मांग-

आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से 65 देशों में 92 परियोजनाओं के लिए 73 मिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किए थे।

9. निष्कर्ष

अफ्रीका में भारत का दक्षिण-दक्षिण विकास सहयोग उपनिवेशवाद-विरोधी एकजुटता और तकनीकी सहायता से विकसित होकर व्यापक रणनीतिक विकास साझेदारी में बदल गया है। इस परिवर्तन को भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन प्रक्रिया, विस्तारित ऋण-व्यवस्थाओं, क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों, स्वास्थ्य कूटनीति, डिजिटल पहलों, व्यापार और निजी क्षेत्र की भागीदारी ने गति दी है।

भारत के दृष्टिकोण में कई महत्त्वपूर्ण खूबियाँ हैं। यह क्षमता-निर्माण, व्यावहारिक विकास अनुभव, किफायती तकनीकों, संप्रभुता के सम्मान और साझेदारी-केंद्रित भाषा पर बल देता है। हालांकि, इसे वित्तीय पैमाने, परियोजनाओं में देरी, समन्वय संबंधी चुनौतियों और अन्य बाहरी शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा जैसी गंभीर सीमाओं का भी सामना करना पड़ता है।

अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का भविष्य घोषित प्रतिबद्धताओं की संख्या से कम और उनके क्रियान्वयन की गुणवत्ता से अधिक निर्धारित होगा। भारत को परियोजनाओं को कुशलतापूर्वक पूरा करना, पारदर्शिता बढ़ाना, अफ्रीकी औद्योगीकरण का समर्थन करना और यह सुनिश्चित करना होगा कि सहयोग की दिशा अफ्रीकी प्राथमिकताओं से तय हो। एक सतत भारत-अफ्रीका साझेदारी वही होगी, जिसमें विकास सहयोग न केवल भारत की कूटनीतिक उपस्थिति को मजबूत करे, बल्कि अफ्रीका की संस्थागत क्षमता, आर्थिक स्वायत्तता और वैश्विक शासन में उसकी आवाज़ को भी सशक्त बनाए।

संदर्भ

1. African Union. 2024. Protocol to the Agreement Establishing the African Continental Free Trade Area on Digital Trade. https://au.int/en/treaties/protocol-agreement-establishing-african-continental-free-trade-area-digital-trade
2. African Union. n.d. The African Continental Free Trade Area. Accessed July 4, 2026. https://au.int/en/african-continental-free-trade-area
3. Boston University Global Development Policy Center. 2026. Chinese Loans to Africa Database. https://www.bu.edu/gdp/chinese-loans-to-africa-database/
4. Brookings India. 2015. “Enhancing India–Africa Development Cooperation.” Brookings Institution. https://www.brookings.edu/articles/enhancing-india-africa-development-cooperation/
5. Confederation of Indian Industry. 2025. India Africa Report 2025. https://www.cii.in/International_ResearchPDF/India%20Africa%20Report%202025.pdf
6. Export-Import Bank of India. n.d. “Lines of Credit.” Accessed July 4, 2026. https://www.eximbankindia.in/lines-of-credit
7. Export-Import Bank of India. 2025. Unlocking Africa’s Sustainable Growth: India’s Role and Prospects. https://www.eximbankindia.in/sites/default/files/2025-07/209file.pdf
8. Government of India, Ministry of External Affairs. 2009. Pan African e-Network Project. https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Pan_African_e_docx_for_xp.pdf
9. Government of India, Ministry of External Affairs. 2021. “Remarks by Shri V. Muraleedharan at the 16th CII-EXIM Bank Conclave on India-Africa Project Partnership.”

https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl%2F34017%2FRemarks+by+Shri+V+Muraleedharan+Minister+of+State+for+External+Affairs+at+the+16th+CIIEXIM+Bank+Conclave+on+IndiaAfrica+Project+Partnership=

10. Government of India, Ministry of External Affairs. 2026a. India–Africa Relations. https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Africa-India-Background-Brief-Final.pdf
11. Government of India, Ministry of External Affairs. 2026b. "Lines of Credit for Development Projects." https://www.mea.gov.in/lines-of-credit-for-development-projects
12. Mukhopadhyay, Abhijit. 2022. "India's Lines of Credit, Development Cooperation, and G20 Presidency: A Primer." Observer Research Foundation. https://www.orfonline.org/research/india-s-lines-of-credit-development-cooperation-and-g20-presidency-a-primer
13. Qazi, Bilal Habib, Hussain Abbas, and Irfan Hasnain Qaisrani. 2025. "Explaining India's Africa Policy: Power Ambitions and Pro-Active Strategies." Humanities and Social Sciences Communications 12. https://www.nature.com/articles/s41599-025-05279-9
14. Research and Information System for Developing Countries. 2015. India–Africa Partnership towards Sustainable Development. https://www.ris.org.in/sites/default/files/India_Africa_Partnership_Towards_Sustainable_Development_Report.pdf
15. Sachdeva, Gulshan. 2020. India–Africa Development Partnership Dynamics. FIDC Discussion Paper no. 3. https://fidc.ris.org.in/sites/fidc.ris.org.in/files/Publication/FIDC_DP-Gulshan-Sachdeva.pdf
16. United Nations General Assembly. 2019. Buenos Aires Outcome Document of the Second High-Level United Nations Conference on South–South Cooperation. A/RES/73/291. https://digitallibrary.un.org/record/3801900
17. United Nations Office for South-South Cooperation. n.d. "About South-South and Triangular Cooperation." Accessed July 4, 2026. https://unsouthsouth.org/about/about-sstc/
18. United Nations Office for South-South Cooperation. 2026. "India-UN Development Partnership Fund Board Advances Results, Partnerships and Impact." https://unsouthsouth.org/2026/04/02/india-un-development-partnership-fund-board-advances-results-partnerships-and-impact/